उपाध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह एक पूरक बजट है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर दे रहे हैं।

12.04 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव— जारी

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद कुल मिला कर बहुत रचनात्मक तथा दिलचस्प रहा है तथा इसे इतना अधिक रचनात्मक बनाने के लिए इसमें भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं शुक्रिया करता हूं। मैं विशेषतौर पर विपक्ष के सदस्यों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने कुछ न कह कर इस वाद-विवाद को रचनात्मक बना दिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्हें अपनी ओर से बधाइयां भेज दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेहरबानी करके कोई टिप्पणी मत कीजिए ।

श्री राजीव गांधी : मैं उनकी टिप्पणियों का जवाब दे सकता हूं ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : प्रधान मंत्री अन्य लोगों के भाषणों पर टिप्पणी करने के शौकीन हैं ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, एक प्रश्न समझौते करने तथा आमने-सामने बैठकर मतभेदों को दूर करने के बारे में उठाया गया था। यद्यपि सभा के बाहर मैं विस्तार से स्पष्टीकरण कर चुका हूं लेकिन चूंकि यह बात सभा उठाई गई है, इसलिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि हम कुछ बातें सभा में ही स्पष्ट कर दें ।

हमने पंजाब समझौते, असम समझौते तथा मिजोरम समझौते की आलोचनाएं सुनी हैं और इसी परम्परा में इन्दिरा जी द्वारा 1975 में शेख साहब के साथ किए गए समझौते की याद दिलाना प्रासंगिक है। मैं पंजाब समझौते में से एक वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

> "इस समझौते से विवाद के युग का अन्त होगा और सौहार्द, सद्भाव एवं सहयोग के एक नये युग का प्रारम्भ होगा जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी।"

मैं विशेषतौर पर इसे उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने सभी विपक्षी

दलों, पंजाब के सभी राजनैतिक दलों तथा हमारे अपने दल ने मिलकर इकट्ठा प्रयास किया है। किस बात के लिए ? इससे पहले कि मैं 'किस बात के लिए' पर आऊं शायद इस बात का अध्ययन करना आवश्यक है कि हम इकट्ठे मिलकर कैसे कार्य कर रहे है तथा हम इकट्ठे मिलकर कार्य कैसे कर पाए है। यदि कोई समझौता नहीं किया गया होता, तो यह सम्भव नहीं हुआ होता। यह केवल तभी सम्भव हुआ है क्योंकि पंजाब में प्रजातान्त्रिक सरकार है। यही कारण है कि यह सम्भव हुआ है। समझौते के प्रत्येक पहलू को पूरा करना कठिन हो सकता हैं। हां, हमारे सामने कठिनाइयां हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं। हमारी ओर से मैं कह चुका हूं कि हम समझौते को लागू करने के किए तैयार हैं। परन्तु कुछ कठिनाइयां हैं, चाहे ये राज्यों में हों या अन्य कहीं हों। एक समझौते के सम्बन्ध में मुख्य बात यह नहीं है कि क्या यह बारीकी पूरी की गई है या वह बारीकी पूरी की गई। मुख्य बात यह है कि कई सदस्य जो आज इस सभा में बैठे हैं, विशेषतौर पर विपक्षी सदस्य, इस सभा में नहीं बैठे होते यदि यह समझौता नहीं किया गया होता। ये समझौते हमारी समस्याओं को हल करने में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को आगे लाने में मुख्य रूप से अग्रणी रहे हैं। इनकी निन्दा नहीं की जानी चाहिए।

माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि यह नहीं किया गया या वह नहीं किया गया। यदि यह समझौता नहीं किया गया होता तो यह प्रश्न उठाने के लिए हम यहां नहीं होते। इसलिए, हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। (व्यवधान) दत्त जी, मैं पश्चिम बंगाल पर बाद में आऊंगा। (व्यवधान) चिन्ता मत कीजिए, मैं पश्चिम बंगाल पर आऊंगा।

श्री अमल दत्त : वहां चुनाव है।

श्री राजीव गांधी : ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए मैं आपको काफी समय दूंगा।

श्री अमल दत्त : प्रधान मंत्री जी, आप किसके ब्लड प्रेशर के बारे में चिन्तित हैं ? अपने या मेरे ?

श्री राजीव गांधी : आपके ब्लड प्रेशर के बारे में, अपने नहीं।

महोदय, जबकि हम समझौतों में विश्वास करते हैं, मेरे बहुत से विपक्षी सहयोगी केवल कलह में विश्वास करते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : हम नहीं।

श्री राजीव गांधी : और हम इस बात में पक्का विश्वास करते हैं कि भारत जैसे एक बड़े देश पर, भारत जैसी विरासत वाले देश तथा हमारे मूल्यों, जिनको हम पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति हमारी विबिधता वाले जैसे देश में शासन लोगों की सम्मति के द्वारा ही चलाया जा सकता है। और विशेषतौर पर प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनैतिक सम्मति लेकर इस देश का शासन चलाने की हम कोशिश करेंगे; तथा मैं उन विपक्ष के सदस्यों का शुक्रिया करता हूं जो पंजाब पर ऐसी सम्मति प्राप्त करने में हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं।

पिछले वर्ष के दौरान पंजाब के बारे में पंजाब की सामाजिक समस्याओं के बारे में इस सभा में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं इस वाद-विवाद, जो पहले ही हो चुका है, के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता तथा उसके पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु आज जब हम मिलकर पंजाब में काम कर रहे है, भारत सरकार का दृष्टिकोण उचित ठहरता है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। हमने जितना समर्थन किया था, पंजाब सरकार को जो समर्थन हमने दिया है, आज, काफी समय के बाद, लाभकारी सिद्ध हो रहा है जब हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की ताकतें, धर्म तथा राजनीति को अलग रखने वाली ताकतें एकजुट होकर फूट डालने वाली प्रवृत्तियों, आतंकवाद, रूढ़िवाद तथा उन ताकतों के विरुद्ध खड़ी हैं जो देश को तबाह करने में लगी हुई है। और मैं इस सभा के सभी दलों का पंजाब में इस संघर्ष में सहयोग देने के लिए पुनः शुक्रिया करता हूं।

पंजाब असम, मिजोरम समझौतों को हमने लागू कर दिया है। हां, समझौतों में कुछ बातें हैं जो पूरी नहीं की गई हैं। परन्तु मेरा दृष्टिकोण कि हमारे पास लम्बित कुछ भी नहीं है, हम किसी भी चीज को नहीं रोक रहे हैं, हम केन्द्र सरकार की ओर से किसी भी चीज में बाधा नहीं डाल रहे हैं, अब भी बरकरार है। मैं जानता हूं कि असम से आने वाले माननीय सदस्य उत्तेजित हो गये हैं। और आज दोपहर बाद मैं मुख्य मंत्री महोदय से मिलने वाला हूं। इसमें संदेह नहीं है कि उनके साथ बैठक के बाद मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूंगा कि हमारी ओर से कुछ भी विचाराधीन नहीं है। अगर कुछ शंकाएं हैं तो उन्हें हम आज दोपहर को दूर कर देंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : लेकिन प्रधान मंत्री जी—भाषण में मैंने आपको बताया था—दुर्भाग्य से आप उपस्थित नहीं थे—कि जो प्रश्न हमने पूछे थे जो सहायता हमने मांगी थी खंड 5(4), खंड 7 आदि के अन्तर्गत उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। आशा है आप इसका स्पष्ट उत्तर देंगे क्योंकि देश भर में आपने यह धारणा बना दी है कि केन्द्र सरकार ने सब कुछ कर लिया है। मैंने बताने की कोशिश की है कि···(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : मैं इस मामले को यहां उठाना नहीं चाहता क्योंकि इस पर हम आज दोपहर चर्चा कर रहे हैं। हमने जो किया है अगर उसके प्रति मैं कठोर रुख अपना लूं तो आज दोपहर होने वाली चर्चा बेमतलब हो जाएगी। और अभी मैं ऐसा करना नहीं चाहता।···

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : इसे निजी वार्ता क्यों माना जाए ? आप सदन को विश्वास में क्यों नहीं लेते ?

श्री राजीव गांधी : क्योंकि आज शाम होने वाली चर्चा के सम्बन्ध में मैं सदन को विश्वास में नहीं ले सकता। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं ऐसा कर दूंगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं नहीं चाहता कि आप सदन को विश्वास में लें। लेकिन मुझे आशा हैं कि आप इस बात को सुधार देंगे कि केन्द्र सरकार को जो करना था उसने कर लिया है

तथा श्री चिंतामणी पाणिग्रही ने यह जो कहा हैं कि केन्द्र सरकार जो करना को है उसका 90% कर लिया गया है, और कृपया उसे भी सुधार दीजिए···(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : कुछ मामलों में, उदाहरण के लिए, हमें जो करना था, उससे भी अधिक किया गया है···

श्री दिनेश गोस्वामी : लेकिन कुछ मामलों में···(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : शेष पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी तरफ से कुछ भी विचाराधीन नहीं है। इसे मैं आज बहुत स्पष्ट ढंग से साफ कर दूंगा। अगर मुख्य मंत्री चाहते है तो हम सार्वजनिक वक्तव्य देंगे और सभा पटल पर रख देंगे···(**व्यवधान**) मुख्य मंत्री और हमारे बीच वार्ता होने दीजिए फिर हम निर्णय ले लेंगे कि इस पर किस प्रकार कार्यवाही करनी है। और अगर हम महसूस करते हैं कि इसे सार्वजनिक बनाया जाना चाहिए क्योंकि अन्ततः हम चाहते क्या हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : कोई परस्पर बातचीत नहीं···

श्री राजीव गांधी : अन्ततः इसे वाद-विवाद का मुद्दा बनाने का सवाल नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी : बिल्कुल नहीं···

श्री राजीव गांधी : सवाल असम में स्थिति को सामान्य करने का है। मैं बताता हूं कि क्या स्थिति हैं···(**व्यवधान**) मैं बताऊंगा किस किस्म की समस्या है। कुछ समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब उग्र राष्ट्रवाद पनपना शुरू हो जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। बहरहाल, समस्याएं होगीं। लेकिन समझौते में यह नहीं कहा गया कि इसे उस तरह से लागू किया जाएगा जिस तरह असम सरकार चाहती है। समझौते में कहा गया है कि किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा होगी। तो एकदम से इस निष्कर्ष पर मत पहुंचिए कि जो आप कहेंगे वही हम करेंगे क्योंकि हम अपने हित के लिए या आपके हित के खिलाफ करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

हम इस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं जो देश के हित में हो, असम के हित में हो···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ··

(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं अपनी बात जारी रखूंगा ··

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी बात को जारी रखेंगे।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : गोस्वामी जी, बैठ जाइए···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा···

(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : महोदय, हम उससे नहीं हटेंगे जो समझौते में लिखा हुआ हैं। मुझे उसे दोहराने दीजिए। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जिससे इस देश की एकता को खतरा हो या एकता कमजोर पड़े। इस बारे में मुझे स्पष्ट कर लेने दीजिए···(**व्यवधान**) मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सम्प्रदायिकतावाद एक ऐसा पहलू है जो इस सदन में हर वर्ग की चिंता का विषय है, जो हमारे देश के हर वर्ग की चिंता का विषय है। इससे सारे देश को खतरा है तथा सम्प्रदायिकता के खतरे का सामना करते समय पक्षपातपूर्ण ढंग से विचार नहीं किया जा सकता। हमें धर्म या सम्प्रदायिकता के अन्य रूपों के बलबूते पर अपनी ताकत बनाए रखने का प्रयास करने वाले कुछ थोड़े से धर्मान्धों, कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को हराने के लिए सम्प्रदायिकतावाद का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर लड़ना है। हमें बहुत सतर्क रहना है और एकजुट होकर काम करना हैं जैसा कि हम पंजाब में इस बुराई का सामना करने के लिए कर रहे हैं। पंजाब में हमने दिखा दिया है कि हम महत्वपूर्ण मसलों पर दलगत मतभेदों से ऊपर उठ सकते हैं और हमें उठना भी चाहिए। हमें एकजुट होकर पूरी तरह से इस खतरे का सामना करना है। मेरे विचार से राष्ट्र आज धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए एक पूरी चर्चा करने और उससे निकले निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए तैयार है। मैं विपक्ष के साथ, किसी के साथ ऐसी चर्चा को शुरू करने, उसमें भाग लेने के लिए तैयार हूं क्योंकि इस पिशाच का सामना हम सबको मिलकर करना है। आशा है इन मामलों को प्रकाश में लाने और सम्भवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इनको ठोस रूप में प्रकाश में लाने में सदन के सभी वर्गों का सहयोग मिलेगा। ऐसा न हो कि लम्बी चौड़ी चर्चा करके इस विषय को आकर्षक बना दिया जाए, परन्तु परिणाम कुछ न निकले। यही अवसर है जब इन मामलों को ठोस रूप दिया जाए और धर्म और राजनीति को अलग करने और राजनीति प्रणाली में धार्मिक निकायों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। कोई परिभाषा बनाना और अपेक्षित उत्कृष्टता लाना मुश्किल है लेकिन अगर ऐसा करना मुश्किल भी है तो भी मेरे विचार से एकजुट होकर लिखित में कुछ करने और···समाप्त

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने का यही समय है···(**व्यवधान**) हम आपके किसी भी सुझाव का स्वागत करते हैं बशर्ते कि रचनात्मक हो···(**व्यवधान**)

श्री के० वी० शंकर गौड (मांड्या) :···बशर्ते की सरकार उन्हें लागू करने के प्रति गम्भीर हो···(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ है और कुछ दिन पहले ही, बजट प्रस्तुत करते समय मैंने अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख किया था लेकिन शायद अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता का सबसे बड़ा प्रतीक विरोधी पक्ष की हताशा है। (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : आप उस हताशा की गहनता को कैसे मापते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : अर्थव्यवस्था के परिणामों से हमारी नीतियों का तथा इस बात का पता चलता है कि जो परिवर्तन हम लाए हैं वे सही हैं।

एक महत्वपूर्ण बात, जिसे मैं पिछले दो सालों से दोहरा रहा हूं लेकिन जिसे फिर से कहना जरूरी है वह है समाजवाद का सवाल। जैसा कि पण्डित जी ने कहा था समाजवाद का अर्थ गरीबी का प्रसार नहीं है। समाजवाद का अर्थ है और अधिक बराबर वितरण, और लोगों का उत्थान और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम समाजवाद की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब उत्पादन अधिक हो, बांटने के लिए अधिक सम्पत्ति हो। तभी हम अधिक सम्पत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। हमें उस सम्पत्ति का निर्माण करना है। इन पिछले दो सालों में हमने दिखा दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन है और वह इस तरह का विकास करने में समर्थ है। हमें पंडितजी द्वारा जारी कार्यनीति को जारी रखना है। इन्दिरा जी हमें जिस रास्ते पर लाई हैं हमें उसी राह पर चलना है। पंडित जी ने अपने प्रधानमंत्री काल के 15-16 वर्षों में, और इन्दिरा जी ने प्रधानमंत्री पद पर अपने 16-17 साल के दौरान कुछ कार्यक्रमों में, उनके निहित आधारभूत विचारधारा को दिलो-दिमाग में रखते हुए सुधार किया था वैसा ही आज करने की जरूरत है। आज यह कहने से कोई फायदा नहीं है कि छठे दशक में पंडित जी ने कहा था कि इस्पात संयंत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं। जी हां, इस्पात संयंत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं पर पंडित जी ने इस्पात संयंत्रों की शुरूआत इसलिए की थी क्योंकि वे वक्त की मांग थे। उसके पीछे यह विचारधारा थी कि प्रौद्योगिकी की जरूरत है। इस्पात संयंत्र, जिसे उन्होंने भारत के नए मन्दिर कहा था, उस विचारधारा की अभिव्यक्ति मात्र थे। आज विचारधारा वही है पर प्रौद्योगिकी के बदलने, भारत के प्रगति करने तथा हमारी जरूरतों में परिवर्तन आने से अभिव्यक्ति में परिवर्तन आ गया है। हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि राष्ट्र की शक्ति, भारत की एकता और अखण्डता, हमारी आत्म निर्भरता उन आदर्शों में से हैं जो हमारे विकास का आधार हैं। हम उन आदर्शों से हटना नहीं चाहते परन्तु समय के साथ-साथ हम उन आदर्शों की स्पष्ट कर लेंगे। हमने दिखा दिया है कि हम उन आदर्शों, उन विचारधाराओं से जुड़े रहने के कारण हम तीन सालों में विकास की दर 8 प्रतिशत से अधिक कर सके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ हैं।

एक दिन मैं सदन में बैठा हुआ था और एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। और वे संख्याओं के बारे में बहुत भ्रम में थे। मैं उनके दिमाग पर बोझ डालना नहीं चाहता। लगता हैं उस पर पहले से ही काफी बोझ है।

श्री अमल दत्त : नई और पुरानी सिरिज के बीच···(**व्यवधान**) आपने पुरानी सिरीज की 95 मदों को नई सिरीज से अलग क्यों रखा है, नई सिरीज में क्यों नहीं रखा हैं ? (**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : मैं देश के कुछ हिस्सों में विकास की कम दर के लिए उत्तरदायी नहीं हूं।

श्री अमल दत्त : बहुत खूब।

श्री राजीव गांधी : माननीय सदस्य उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तभी वहां पर अपनी स्थिति को ध्यान में रखकर वे ऐसा कह रहे हैं।

श्री अमल दत्त : जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं वे देश के साथ धोखा हैं।

श्री राजीव गांधी : महोदय, अगर माननीय सदस्य वास्तव में उत्तर चाहते हैं तो वे आंकड़े-वार उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर माननीय सदस्य महसूस करते है···(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : पुराने उद्योगों को क्या हुआ ? क्या वे खत्म हो गए ? 95 उद्योगों को निकाल दिया ? क्या आपको इसका पता है (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अमल दत्त जी, हस्तक्षेप मत करिए।

श्री राजीव गांधी : कुछ उद्योग जैसे पेट्रोलियम, इलैक्ट्रानिकी·· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने का हक है। जब आपको समय दिया गया था तो आप भी बोल रहे थे।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : मेरा नाम लिए बिना वह मेरा उल्लेख कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : माफी चाहता हूं। मैंने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया। उन लोगों का पता लगाना मेरा काम नहीं है जो संशय में होने के कारण अपराध बोध महसूस करते हैं। (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : पता लगाना बहुत मुश्किल हैं।

श्री राजीव गांधी : अगर टोपी ठीक आती है तो सिर के आकार के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हो सकता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : प्रधानमंत्री जी पं० बंगाल की चर्चा मत करिए। नहीं तो कुमारी ममता बनर्जी या वह गुस्सा हो जाएंगे।

श्री राजीव गांधी : महोदय, हमारे पश्चिम बंगाल के सभी सदस्यों की चुनाव अभियान के लिए आवश्यकता है । कुछ सदस्यों को राज्य से बाहर रखा जाना पसन्द किया गया है । **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : यदि प्रधानमंत्री होते हुए वह ऐसा कहें तो यह संसद के लिए अपमानजक है। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं । **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : नहीं, नहीं आप मुझे ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, आप राष्ट्र को ठेस पहुंचा रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दत्त, इसे सहजभाव में ले लें ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, मेरा मतलब माननीय सदस्य को ठेस पहुंचाने से नहीं था ।

श्री अमल दत्त : तब आपका ठीक-ठीक आशय क्या है ? चुनाव अभियान संसद में हाजिर होने से अधिक महत्वपूर्ण है ? सही मायने में यही आपका मतलब है ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, इस तरह से पेश न आएं ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, यदि मैंने माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं माननीय सदस्य से क्षमा मांगता हूं । लेकिन यदि वे इस बात से क्षुब्ध हैं कि उन्हें चुनाव अभियान में नियंत्रित नहीं किया है गया तो हम उन्हें चुनाव अभियान में नियंत्रित करना चाहते हैं, बशर्ते कि किसी ने भी उन्हें नियंत्रित नहीं किया है । **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : प्रधानमंत्री होने के नाते आपका इस तरह कहना उचित नहीं है । यह संसद की गरिमा को कम करता है । कृपया संसद की गरिमा को ऊपर उठाने की कोशिश करें ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, यह एक खुला निमंत्रण है तथा माननीय सदस्य इसे स्वीकार करना चाहें तो मैं उनसे इस वाद-विवाद के बाद बात करूंगा ।

महोदय, हमने दिखा दिया है कि हम सरकारी क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार लाकर, इसके कार्यकरण, कार्य-निष्पादन में सुधार लाकर अपनी अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अभी आगे बहुत भारी चुनौतियाँ हैं । यह कोई आसान कार्य नहीं है तथा समय देश में सबसे बड़ी चुनौती एक नया दृष्टिकोण लाने के बारे में है और यह न केवल उद्योग में जरूरी है जो कि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी आवश्यक हैं जोकि अर्थव्यवस्था का और अधिक महत्वपूर्ण, अंग है, लेकिन शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सरकार की कार्यकरण की शैली में नया दृष्टिकोण लाने के बारे में हैं । मैंने यह बात अपने बजट भाषण में उठाई थी और हम इसमें बहुत गहराई में जाना चाहते हैं । मैं जल्दबाजी में

दिए उत्तरों तथा तैयार उपायों में विश्वास नहीं रखता हूँ। यह एक काफी लम्बा कार्यक्रम है। इसके लिए स रकार को तथा सरकारी संगठनों को, केन्द्र में ही नहीं अपितु राज्य और जिला स्तर पर भी अपने कार्य का ढंग पूरी तरह बदलना होगा, जहाँ कि अधिक कठिनाईयाँ हैं, इसलिए जितने निचले स्तर पर आप जायेंगे उतना ही स्वयं को समस्या के निकट पायेंगे। और यदि हमें इस कार्य में सफल होना है तो हमें सदन के प्रत्येक वर्ग से पुन: सहयोग की आवश्यकता होगी। यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे केवल सरकार पर ही छोड़ा जा सके। इसमें हमारे सभी लोगों का सम्मिलित होना आवश्यक है। और हम इस विषय पर सदन में, सदन से बाहर कहीं भी किसी भी स्तर पर एक वाद-विवाद करना चाहेंगे तथा एक परिणाम पर पहुंचना चाहेंगे जिससे हमें आशा है कि इस प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। पुनः मैं नहीं चाहता कि यह कार्य तेजी से करने की कोशिश की जाए परन्तु हमें देखना चाहिए कि प्रत्येक कदम उचित दिशा में हो, हमारे कार्यक्रमों की लागत को कम करने की दिशा में हो। जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, जब मैं दूर-दराज के गांवों का दौरा करता हूं तो मुझे शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि हमारे केन्द्रीय कार्यक्रमों में किस तरह फेर-बदल की जाती है और किस शक्ल में वे निचले स्तर पर पहुंचते है। निस्सन्देह ऐसा होता है तथा इससे हम इन्कार नहीं करते हैं परन्तु इसे ठीक करने के लिए इस पर यहाँ हो-हल्ला करना, उपयुक्त नहीं है। वही आरम्भिक बिन्दु है। हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, रुकावटें क्या है, समस्यायें क्या है और उत समस्याओं को समझने तथा हटाने की कोशिश करनी चाहिए। लागतें बहुत ऊंची हैं। यह केवल लक्ष्यों से ही हटाने का प्रश्न नहीं है। कार्यक्रमों की लागत या इसका क्रियान्वयन बहुत खर्चीला है, इस कार्यक्रम का लागू करने पर ही इतना खर्च है कि जब तक यह कमजोर वर्गों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को अन्य कम सुविधा वाले वर्गों को लिए जाने के दिए तैयार होता है तब तक उस कार्यक्रम में प्रशासनिक खर्च को काट कर क्या रह जाता है केवल उसका एक बहुत थोड़ा हिस्सा, जिससे हमने इस कार्यक्रम का आरम्भ किया था। इसलिए अपने कार्य करने के ढ़ंग में सुधार का, यही अगला कदम हमें लेना है। सरकार ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वह इसे हल करने में लगी है और इस कार्य को हल करने के लिए हम सारे राष्ट्र का पूर्ण सहयोग चाहते हैं।

कृषि के क्षेत्र में जितना हम चाहते थे उतना विकास नहीं हुआ है। हमने सिचाई, बिजली, उर्वरकों तथा कृषि में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजों पर काफी धन लगाया है, किसानों को पहले से कहीं अधिक उनकी उपज का मूल्य दिया है, किन्तु फिर भी उतना उत्पादन नहीं बढ़ रहा है जितना कि बढ़ना चाहिए था। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किए *जाने की आवश्यकता है। हम* इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

हमारे यहाँ कई वर्षों तक सूखा पड़ता रहा है। विभिन्न राज्यों के अनेक सदस्य इस प्रश्न को उठाते रहे हैं और इसने हमारे कृषि विकास में भी रुकावट डाली है। लेकिन इन अनेक सूखों तथा बाढ़ों के कारण हुई क्षति के बावजूद हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है ये ठीक हैं कि उतना नहीं बढ़ा है जितना हम बढ़ाना चाहते थे लेकिन फिर भी यह इन कठिनाईयों तथा प्रकृति के हमारे अनुकूल न होने के बावजूद बढ़ा है। खाद्य स्थिति बहुत अच्छी हैं। हमने कठिनाई में पड़े उन वर्गों के

लिए कार्य देने के लिए काफी मात्रा में खाद्यान्न का इस्तेमाल किया है। मैं अपने किसान भाईयों का, अपने कृषि प्रौद्योगिकीविदों तथा जो लोग कृषि से जुड़े है उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि खराब वर्षा के कारण उत्पन्न इन कठिनाईयों के बावजूद उन्होंने इतना उत्पादन करके दिखाया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम तीन वर्षों में किसी भी अन्य योजना से अधिक धन का नियतन किया गया है। हम पहली बार पहले तीन वर्षों में योजना का 63 प्रतिशत भाग पूरा कर रहे हैं। यह सरकार की एक अन्य बड़ी उपलब्धि है।

सार्वजनिक क्षेत्र में हमारा निवेश पहले किन्हीं दो वर्षों से ज्यादा है। इससे यह भी पता चलता है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र को कितना महत्व देते है। यह हमारी योजना का हिस्सा है, यह हमारी विकास प्रक्रिया का भाग है और इसके महत्व को कम करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। सातवीं योजना में हमने गरीबी निवारण कार्यक्रमों को बड़ा महत्व दिया है। जो राशि हमने गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए नियत की है वह पहले से कहीं अधिक है। जैसे कि मैंने बजट भाषण में कहा था, इस वर्ष हमने ग्रामीण विकास के लिए दो हजार करोड़ रुपए नियत किए हैं। इसकी तुलना छठी योजना की 3600 करोड़ रुपए की कुल नियत धनराशि से की जा सकती है। और इन दो वर्षों में अर्थात 1986-87 और 1987-88 में हमने विकास के लिए छठी योजना की कुल राशि से अधिक धन नियत किया है। इससे इस बात का पता चलता है कि हम ग्रामीण विकास तथा गरीबी मिटाने को कितना महत्व देते हैं।

श्री अमल दत्त : आप हमें अवमूल्यित आंकड़े दीजिए, पैसे की कीमत गिर गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ?

श्री राजीव गांधी : मैं आपको आगे कुछ और आंकड़े देकर आश्चर्यचकित करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त···

श्री अमल दत्त : मैं आपकी बात से संशय में नहीं पड़ना चाहता हूं। इसी वजह से आपने अवमूल्यित आंकड़े दिए है और इनकी तुलना की है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दूंगा। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हम गरीबी निवारण कार्यक्रम को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी लेते हैं। गरीबी निवारण कार्यक्रमों को केवल वर्तमान कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है और नहीं उन्हें सीधे सहायता दी जा सकती है क्योंकि एक सीमित क्षेत्र के अन्दर इतना ही संभव

है, चाहे हम इसके लिए कितनी भी धनराशि नियत करें। हमने इस वर्ष 2000 करोड़ रुपये नियत किये हैं जोकि एक बहुत बड़ी राशि है। लेकिन चाहे हम कितना भी धन नियत करें, आंकड़े हमेशा ऐसे होने चाहिए कि हम वास्तव में उन लोगों तक पहुंच सकें जोकि निचले स्तर पर हैं और वे जोकि बहुत निर्धन है। शेष अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए हमें गरीबी निवारण कार्यक्रम को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए तथा वह व्यापक परिप्रेक्ष्य औद्योगिक विकास है, कृषि विकास है। क्योंकि वहीं वास्तविक गरीबी निवारण कार्यवाही चल रही है। हम केवल उन्हें सहायता देते है जो बहुत गरीब है तथा गरीबी निवारण के हमारे कार्यक्रमों के द्वारा दी जा रही हमारी सीधी सहायता का फायदा उठाने में समर्थ नहीं हैं।

शायद गरीबी निवारण कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारा शिक्षा कार्यक्रम है। बिना शिक्षा के गरीबी दूर नहीं की जा सकती है। हम सहायता दे सकते हैं, और सब कुछ कर रहे हैं लेकिन यदि हम अपनी इस पीढ़ी के साथ इन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर सकते हैं, तो अगली पीढ़ी को भी ऊपर नहीं उठा सकते हैं। हमारा प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक मुख्य कार्यक्रम है परन्तु हम इस कार्यक्रम की सीमाओं से अवगत हैं। लेकिन हमें कम से कम···(व्यवधान) दुर्भाग्य से कुछ सदस्यों को इनके बारे में कतई जानकारी नहीं है और मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं।

श्री अमल दत्त : आपका क्या कार्यक्रम है ? प्रौढ़ शिक्षा के लिए बहुत थोड़ी धनराशि नियत की गई है।

श्री राजीव गांधी : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है, हमारा इस पर एक प्रौद्योगिकी मिशन है।

श्री अमल दत्त : इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। उन बातों का राग न अलापिए जिन्हें सरकार प्राप्त नहीं कर सकती है।

श्री राजीव गांधी : हम आज इस्पात का उत्पादन केवल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि 1950 के शुरू में पंडित जी ने इसकी नींव रखी थी। आप एक कार्यक्रम शुरू करें···

श्री अमल दत्त : आपका इस्पात का उत्पादन उतना ही है जितना 1960 के शुरू में था।

श्री राजीव गांधी : सिवाय बंगाल के जहाँ शायद इसका उत्पादन घट रहा है। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : आप केवल उसी समय उपस्थित थे, जब वह अपना भाषण दे रहे थे। यह बात कठिनाई पैदा कर रही हैं।

श्री राजीव गांधी : नहीं, मैं वहां कुछ अन्य भाषणों के वक्त भी उपस्थित था। परन्तु सौभाग्य से अन्य अनुशासित थे और वे अपनी समय सीमा में रहें, जबकि कुछ अन्य सदस्य केवल अपनी ही बातें कहते चले गये और उन्होंने सभा का समय बर्बाद किया।

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : आपका ज्यादा समय श्री अमल दत्त पर खर्च हो रहा है।

श्री राजीव गांधी : आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम उन्हें चुनाव अभियान के लिए भेजेंगे।

शिक्षा गरीबी निवारण कार्यक्रम का आधार है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खाँ (एटा) : हम लोगों को भी क्यों शामिल कर रहे है, आपकी और अमल दत्त साहब की बात है ?

श्री राजीव गांधी : आपको ही बता रहे हैं, एजूकेशन के बारे में। हमारी उम्मीद है कि आपको बताते-बताते दूसरे कुछ लोग भी सीख जायें।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : यह सही है।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : शिक्षा हमारे विकास की धुरी है। विश्व में जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है इसका महत्व बढ़ता ही जाता है। मैं इसके बारे में अन्य राज्याध्यक्षों से बात करता रहा हूं। यह ऐसी समस्या नहीं है जोकि भारत तक ही सीमित हो। सब जगह यह समस्या विद्यमान है, इसके आयाम अलग हो सकते हैं, प्रकार भिन्न हो सकते है लेकिन समस्या का आधार एक ही है। प्रौद्योगिकी, उद्योग तेजी से विकास करते हैं। यदि हमारे श्रमिक हमारी युवा पीढ़ी समान रूप से शिक्षित नहीं हो पाती है या समान दर से शिक्षित नहीं हो पाती है तब वे पीछे रह जायेंगे। हमारा अधिक आत्मविश्वास इस पर निर्भर करता है कि हमारी जनता के मन में आज की समस्याओं का सामना करने के लिए कितना विश्वास है। हमें यह फैसला करना होगा कि क्या हम अपने उन्हीं उद्योगों को चलाते रहें जो आज से 50-60 वर्ष पहले चल रहे थे। क्या यह वास्तव में हमारे श्रमिकों के हित में है कि जो कार्य हमारा श्रमिक 50 वर्ष पहले करता था आज भी करता रहे या उसके हित में यह है कि काम करने के वातावरण में परिवर्तन हो, उसकी दक्षता में सुधार हो, उसकी प्रौद्योगिकी विकसित हो, उसकी जानकारी बढ़े, आधुनिकतम मशीनों पर कार्य करे आदि और पुरानी मशीनों के बजाये अधिक आधुनिक मशीन पर कार्य करे ? हमें अपने दृष्टिकोण को केवल इस तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए कि श्रमिकों का हित केवल उन्हें कुछ अच्छे कपड़े देने से, अच्छा वेतन देने से और शायद एक टेलीविजन सैट और थोड़ा अच्छा भोजन उपलब्ध कराने से ही हैं। ये बहुत ही सीमित परिप्रेक्ष्य वाली बातें हैं। हमें अपनी जीवन-शैली में सुधार करना चाहिए। हमें श्रमिक के काम करने के वातावरण में सुधार करना चाहिए और इसके लिए पूरे उद्योग की गहराई में जाना आवश्यक है और हमारे श्रम संगठनों की विचारधारा में भी एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। (व्यवधान) दत्ता जी मैं आपका उल्लेख नहीं कर रहा था।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : आधुनिकीकरण के लाभ मालिकों को मिल रहे हैं न कि श्रमिकों को। यही कपड़ा उद्योग में हुआ है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : प्रधानमंत्री जी, यह दोनों दल आपके साथ एक साथ लड़ रहे हैं।

[अनुवाद]

डॉ० दत्ता सामन्त : ये लाभ श्रमिकों को दिये जाने चाहिए।

श्री राजीव गांधी : बिल्कुल ठीक बात है। लाभ श्रमिकों को जाना चाहिए। परन्तु हम किन लाभों की बात कर रहे हैं ? यह महत्वपूर्ण है। मैं समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लाभ केवल संशोधित वेतन हैं, या कि हम श्रमिकों के लिए एक अच्छे काम करने के वातावरण की तलाश कर रहे हैं ? क्या हम चाहते हैं कि वह उसी माहौल में काम करे ? मैंने देखा है कि कुछ कपड़ा मिलें कैसे कार्य करती हैं। मैंने देखा है कि काम करने का माहौल कितना भयंकर है। क्या हम उसमें सुधार लाने के लिए कुछ कर रहे है ? नहीं। हम केवल उसकी मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं जो आवश्यक है। मजदूरी आवश्यक है परन्तु मजदूरी ही लक्ष्य नहीं हो सकता। (व्यवधान) मजदूरी पैकेज का केवल एक हिस्सा है जो मजदूर को अवश्य मिलना चाहिए।

श्री अमल दत्त : मुझे कहना चाहिए कि यह एक बहुत स्पष्ट स्वीकारोक्ति है।

श्री राजीव गांधी : शिक्षा ऐसी चीज नहीं है जिसे शैक्षणिक संस्थानों तक ही सीमित रखा जा सके। (व्यवधान) आप अपने को दोषी महसूस क्यों कर रहे है ? मैं एक बहुत गम्भीर मामले पर बोल रहा हूं। दुर्भाग्यवश आप यह बात नहीं समझते हैं। (व्यवधान) शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। शिक्षा ऐसी चीज नहीं है जो आपके स्कूल छोड़ते ही या महाविद्यालय को छोड़ते ही समाप्त हो जाती है। शिक्षा आपके जीवन-पर्यन्त जारी रहनी चाहिए क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो समाज में गतिहीनता आनी शुरू हो जाएगी। एक औद्योगिक श्रमिक के जीवनपर्यन्त यह जारी रहनी चाहिए। उसके कौशल में निरन्तर वृद्धि होती रहनी चाहिए। हमें अपने लोगों में यह निवेश करना चाहिए और यही चीज है जो हमने एक नया विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, बना कर शुरू करने की कोशिश की है। इसके पीछे यह व्यापक सिद्धान्त है। दुर्भाग्य की बात है कि संसाधन का विकास नहीं हुआ है। मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आप हमारे संसाधनों की चोरी कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं ?

श्री राजीव गांधी : मैं उस बात पर भी आऊंगा। हमने शुरूआत कई योजनाओं के साथ की थी। मैं सभी योजनाओं की गहराई में नहीं जाना चाहता। परन्तु, मेरे विचार में एक योजना उल्लेखनीय है। और वह नवोदय विद्यालयों के बारे में है। हमने एक बिल्कुल ही नई प्रणाली शुरू की है। कुछ लोगों ने नवोदय विद्यालयों को अभिजात्य वर्ग के लिए बताया है, उन्होंने सभी तरह की बातें कही हैं। परन्तु, मेरे विचार में मेरे लिए इस बारे में एक बार फिर से बताना

आवश्यक है क्योंकि हमें वही बात सुनने को मिल रही है। अभिजात्य शिक्षा क्या है ? मेरे विचार में अभिजात्यवाद को दो तरह से देखा जाना चाहिए। अभिजात्य वर्ग क्या है ? क्या 'अभिजात्य वर्ग' का सम्बन्ध पैसे से है ? यदि इसका सम्बन्ध पैसे और परिवार विशेष या व्यक्ति विशेष की वित्तीय क्षमता से है तो यह बहुत बुरी बात हैं और हमें शिक्षा प्रणाली में इसका हस्तक्षेप किसी भी तरह से नहीं होने देना चाहिए। परन्तु यदि 'अभिजात्य वर्ग' का सम्बन्ध बुद्धि से है तो मेरे विचार में हमें अभिजात्यवाद को अपनाना चाहिए। हमें देश में बुद्धिमान लोगों को ढूंढ़ना चाहिए। आज हमें देश में बुद्धिमान लोग नहीं मिल रहे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ बुद्धि के लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अपने को शहरी क्षेत्र तक तथा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रख रहे हैं, शायद एक शहरी क्षेत्र के आसपास जिसे बेहतर शिक्षण संस्थान प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली स्पष्ट रूप से अभिजात्य वर्ग के लिए है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान लोगों को ऊपर आने का अवसर नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि लोग धनवान हों केवल तभी प्रतिभावान लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल पाता है। यदि वे गरीब हैं तो उन्हें कोई भी अवसर नहीं मिल पाता। यदि शहरों में वे लोग गरीब है तो वे एन०डी०एम०सी० के विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं अथवा नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं या सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं और स्कूलों का दरजा, अध्यापकों की योग्यता ऐसी नहीं है कि वे बुद्धिमान छात्र का पता लगा सकें। ऐसा नहीं है कि वे यह पता लगा सकें और पता लगाने की कोशिश कर सकें कि कौन सा बच्चा किस विषय में अच्छा है तथा वे उनकी बुद्धि का कैसे विकास करें। आज हमारी शिक्षा प्रणाली में यह क्षमता नहीं है। आज शिक्षा प्रणाली बहुत अभिजात्य है क्योंकि यह प्रणाली बुद्धि की बजाय पैसे तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को अधिक महत्व देती है। यही बात है जिसे हम नवोदय विद्यालयों के जरिए बदलना चाहते हैं। और नवोदय विद्यालयों से हम यह परिवर्तन ला रहे हैं। (**व्यवधान**) शायद शिक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू—और फिर यह एक ऐसी चीज है कि हम एकजुट होकर कार्य करें—नैतिक मूल्य है जो यह हमारे समाज में निर्मित करती है। दुर्भाग्यवश, कारण चाहे कुछ भी हो, हमारा समाज अपने पारस्परिक नैतिक मूल्यों से हट गया है। यह भौतिकवादी मूल्यों की ओर खिसक गया है। यहां तक कि यह बात यहां सभा में भी देखने को मिलती है क्योंकि जब यहां वाद-विवाद होता है, प्रमुख वाद-विवादों में हम क्या चाहते हैं ? हमारी मांगें क्या होती हैं ? वे मांगें वित्तीय मांगें हैं। हमेशा यह वाद-विवाद वित्तीय मांगों, वित्तीय नियंत्रण के साथ समाप्त होता है। इससे हमेशा मूल्यों की भौतिकवादी व्यवस्था ही सामने आती है जिसे हम आज बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे समाज की जड़ें बहुत गहरी हैं ये अध्यात्मवाद और सौन्दर्यबोध और हमारी संस्कृति पर टिकी हुई है जिसके विकास में हजारों वर्ष लगे हैं। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति केवल एक ही संस्कृति नहीं है। यह दस विभिन्न लोगों की संस्कृति है। यह असम की संस्कृति है। यह तमिलनाडू की संस्कृति है। यह हमारी जनजातियों की संस्कृति है। यह···की संस्कृति है···

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल ?

श्री राजीव गांधी : मैं बंगाल का जिक्र अन्त में करने वाला था। यह बंगाल की पारम्परिक

संस्कृति है, यह वह संस्कृति नहीं है जिसे बंगाल की संस्कृति के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही हैं—और यह एक महत्वपूर्ण बात है---वह संस्कृति जिसे हम कभी-कभी प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम इसे एक राजनैतिक परिपेक्ष में देखते हैं, हम इसे एक हथियार के रूप में प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं, एक मंच के रूप में, इसका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ अथवा उन्नति के लिए। जब हम मूल्यों की बात करते हैं तथा अपने नैतिक मूल्यों को वापस प्रतिष्ठित करने की बात करते हैं तो हमें इस धारणा को छोड़ देना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि नई शिक्षा प्रणाली यह कार्य करने में सक्षम होगी। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि जो निर्देश हमने दिए हैं वे ठीक हैं। उनमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी क्योंकि हम अनुभव से सीखते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बना कर छोड़ दें। हमें इस नीति पर काम करना होगा, बहस करनी होगी, चर्चा करनी होगी, इसका विकास करना होगा तथा ज्यों-ज्यों इस नीति का विकास होगा, हमें इसे और परिष्कृत करना होगा। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि सभा के हर एक वर्ग से हमें मूल्यवान सुझाव मिलेंगे और मुझे आशा है कि ये सुझाव हमारी दलगत भावनाओं, क्षेत्रीयता अथवा तुच्छ अतिराष्ट्रीयता से प्रेरित नहीं होने चाहिए। यदि आज देश को मजबूत बनाना है तो हमें इन सब बातों से ऊपर उठना चाहिए और उन मूल्यों को आत्मसात् करना चाहिए जिन्हें, मैं जानता हूं, हममें से प्रत्येक व्यक्ति, जो यहां उपस्थित है, वास्तव में हमारे समाज में पुनः लाना चहता है।

आर्थिक विकास केवल केन्द्र सरकार का ही दायित्व नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम सब मिलकर राज्य सरकारों के साथ कार्य करते हैं। कभी-कभार मुझे बताया गया है कि समन्वय की कमी है। यदा-कदा मुख्य मंत्रियों ने मुझे बताया है कि केन्द्र सरकार प्रस्तावों को स्वीकृति देने में काफी समय लेती है। पहले यह बात पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के बारे में कही गई थी परन्तु हमने उन सभी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है और अब पर्यावरण सम्बन्धी कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। परन्तु मेरे पास शिकायतें भेजी गई हैं और जैसाकि श्री अमल दत्त ने कहा है, वे शिकायतें मेरे सामने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और कई अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने रखी है। यह शिकायत मेरे समक्ष पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने रखी थीं, मैं कलकत्ता एक कार्यक्रम के सिलसिले में गया था तथा उस बैठक में उन्होंने मुझे बताया कि पश्चिम बंगाल की ओर हमारा दृष्टिकोण सौतिली मां जैसा है, केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं और 'केन्द्र सरकार' पश्चिम बंगाल को वंचित रख रही है। इसलिए, मैंने कहा: "ठीक है, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं, हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, हम पश्चिम बंगाल को वंचित नहीं रखना चाहते; हम पश्चिम बंगाल की सहायता करने के लिए हर चीज करेंगे जो हमारे हाथ में है।" इसके शीघ्र बाद ही या तो हमने एक दल पश्चिम बंगाल भेजा या पश्चिम बंगाल से एक दल दिल्ली आया, परन्तु मेरे विचार में दोनों कार्य हुए : बंगाल से एक दल दिल्ली आया था तथा दिल्ली से एक दल बंगाल गया था। सभी समस्याओं, सभी लम्बित समस्याओं, जो हमारे समक्ष उठाई गई थी; के प्रत्येक पहलू पर हमने कई सप्ताह तक गहराई से विचार किया था। इसके बाद मैं बंगाल गया ताकि बैठकर वहां उन सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके जो अभी तक हल नहीं हो पाई थीं और जिनके बारे में कुछ इस तरह के

राजनैतिक निर्णय की आवश्यकता थी कि "ठीक है, अफसरशाही ने जो लालफीताशाही की रुकावट पैदा कर रखी है उसे हम समाप्त कर देंगे और वह कार्यवाही करेंगे जो किसी न किसी कारण से रुकी पड़ी है।" और इस प्रक्रिया के अन्त में हम बंगाल के लिए एक हजार करोड़ रुपए से ऊपर की एक मुश्त सहायता घोषित कर सके। इसे हम बहुत बड़ी कल्पना नहीं समझते थे। यह विचार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ही था जिस पर हम आगे बढ़े। मुझे प्रसन्नता हैं कि बंगाल को इतनी बड़ी एक-मुश्त सहायता देने का निश्चिय कर हम पश्चिम बंगाल की सहायता कर सके हैं···(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : चुनाव प्रचार।

श्री राजीव गांधी : मेरी समझ' में यह बात नहीं आई। अभी कुछ मिनट पहले माननीय सदस्य ने मेरे द्वारा बंगाल को एक हजार करोड़ रुपये दिए जाने पर आपत्ति की। अब वह कह रहे हैं कि बंगाल का एक हजार करोड़ रुपये देना चुनाव प्रचार है···

श्री अमल दत्त : मैं आंकड़ों पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं—तदर्थ 1007 करोड़ रुपये। इस सभा में बहस हुई थी, और जब योजना मन्त्री जवाब नहीं दे सके तो सभा को स्थगित करना पड़ा। आपको ज्ञात होगा कि आपने अपने मंत्री को किस असमंजस में डाल दिया था···

(व्यवधान)

श्री राजीव गाँधी : कुल आंकड़े में गलती होने का प्रश्न ही नहीं है। हम पूरा ब्यौरा दे सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपने बंगाल को एक हजार करोड़ रुपये दिए हैं। बम्बई को एक सौ करोड़ रुपये क्यों नहीं दे देते जिसका आपने वायदा किया है ?

श्री राजीव गांधी : मैं बम्बई के बारे में भी बताऊंगा। राज्य में जाने तथा उसकी समस्याओं का समाधान करने के विचार की शुरूआत बंगाल के मुख्यमंत्री के सुझाव से हुई और इस सुझाव के लिए मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि इससे हमें कई अन्य राज्यों में भी सहायता मिली है। परन्तु इससे पहले भी जब मैंने एक राज्य का दौरा किया तो दौरे के बाद अन्तिम दिन मैंने पाँच या छः घण्टे मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री तथा प्रशासन के साथ बिताये तथा सभी समस्याओं का समाधान किया। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुई है। हमने ऐसा अरुणाचल प्रदेश में किया था, हम ऐसा कई अन्य राज्यों—गुजरात, केरल तथा कई क्षेत्रों में कर चुके हैं। यहाँ मेरे पास उनकी सूची नहीं है। अतः मैं आंशिक सूची नहीं देना चाहता।

यह लालफीताशाही तथ रुकावटों को दूर करने की प्रक्रिया है। और फिर यह राज्य पर निर्भर करता है। क्योंकि एक बार जब हमने एकमुश्त स्वीकृति दे दी तो इस पैकिज का लाभ उठाने का दायित्व प्रायः राज्य सरकार का है। यदि हम एक हजार करोड़ रुपये देते हैं या चार सौ करोड़ रुपये देते हैं और राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं करना चाहती और राज्य सरकार उसका

उपयोग करने की बजाय अभी भी चिल्लाती है तो कार्यान्वियन न करने के बारे में हम क्या कर सकते हैं ? लगभग प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन का भार राज्य सरकार के हाथ में है। यहाँ तक कि हमारी योजनायें तथा कार्यक्रम होते हुए भी बहुत कम परियोजनायें केन्द्र सरकार के पास है। केन्द्र सरकार के लगभग प्रत्येक कार्यक्रम का अन्तिमरूप से निष्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और उन कार्यक्रमों के निष्पादन की कार्यक्षमता ही इस बात का द्योतक है कि लाभग्राहियों को उस कार्यक्रम से कितना लाभ पहुंचता है। यदि कोई राज्य सरकार अकुशल है तो लोगों को कम लाभ मिलता है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : टिप्पणी मत कीजिये।

श्री अमल दत्त : यह तो पूंजीपतियों को धनराशि निर्यात करना है। यदि उन्हें इसकी आवश्यकता है तो वे इसे प्राप्त कर सकते हैं।

श्री राजीव गांधी : महोदय, पूंजीपतियों को धनराशि नियत करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। परन्तु हमने भी देखा है और एक अन्य बात भी बता देना आवश्यक है कि पिछले पांच-छः महीने से कुछ राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर कार्य बन्द कर दिया है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस काम को बन्द क्यों कर दिया है। एक राज्य सरकार ने जिसकी मुझे जानकारी है, कोई भी कार्य नहीं किया है।

श्री अमल दत्त : किस राज्य ने कार्य नहीं किया है ?

श्री राजीव गांधी : जिस पर यह बात उतरती है उसी ने !

एक माननीय सदस्य : आप दोषी क्यों महसूस कर रहे हैं ? प्रधानमंत्री ने किसी राज्य का नाम नहीं लिया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं ? ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए।

श्री राजीव गांधी : भारत की विदेश नीति का लक्ष्य भारत को मजबूत करना है। यदि विश्व में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन मजबूत है तो भारत भी मजबूत है। यदि गुटबन्दी मजबूत होती है, यदि गुट मजबूत होते हैं तो विकासशील अपनी उस स्वतन्त्रता को खो देंगे जो उन्होंने जबरदस्त संघर्ष के बाद प्राप्त की है। यहां तक कि आज भी हम देखते हैं कि, यद्यपि हमने उपनिवेशिक शासन को उखाड़ फैंका है तथा हम स्वतन्त्र हैं, विश्व अर्थव्यवस्था स्वतन्त्र नहीं है जैसा कि हम चाहते हैं।

विश्व अर्थव्यवस्था में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद कई तरह से विद्यमान है। यह अगली चुनौती है जो हमारे सामने है। इस चुनौती का सामना आंखें बन्द करके तथा विश्व में क्या हो रहा है उसको नजरन्दाज करके नहीं किया जा सकता। यदि हम इस चुनौती को नजरन्दाज करते हैं तो भारत अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, भारत उस तरह से खड़ा नहीं रह सकता जैसे वह आज खड़ा है। भारत स्वतंत्र नहीं रहेगा यदि हम विश्व में नये स्वतंत्रता प्राप्त देशों को स्वतन्त्र नहीं बनाये रख सकते।

1.00 म० प०

इस काम से हम बच नहीं सकते। इसका हमें मुकाबला करना चाहिए और उससे लड़ना चाहिए। कुछ सदस्यों की इस भावना को देखकर कई बार दुःख होता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देख कर दुःख होता है कि इस सदन के कुछ सदस्य महसूस करते हैं कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसकी उपेक्षा की जा सकती है; केवल अन्दर झांकों और जीते रहो। इसी रवैये ने हमें गुलाम बनाया था। इसी रवैये ने भारत को महावता के उच्च शिखर से गिराकर दासता तक ला दिया था। इस दृष्टिकोण से आज हमें सतर्क रहना है। आज भारत बहुत से मामलों में विश्व में पहल कर रहा है। हमें इस पहल को बनाए रखना है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। आज हम विश्व के आर्थिक ढ़ांचें में ही परिवर्तन करना नहीं चाहते। यह महत्वपूर्ण है। हमने संघर्ष किया हैं। हमने कड़ा संघर्ष किया है और हम तब भी जीते है जब शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ, जो मुट्ठी भर देशों के खिलाफ एकजुट हो गए थे, हमारा मुकावला हुआ। हम जीते क्योंकि हम सही थे, क्योंकि हमारे पास इच्छाशक्ति थी, क्योंकि हमारे पास दृढ़ता थी। हम सच के लिए लड़े और जीते।

आज उससे भी काफी अधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। चुनौती यह है कि आज विश्व हमें एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखे। हम कहते हैं कि हम एक राष्ट्र हैं, हम जाति, धर्म और भाषाई रुकावटों को समाप्त करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे देश का बंटवारा कर दिया। हमें इस विश्व की मानवता को विभाजित करने वाली अन्य रुकावटों को भी दूर करना है। जब हम विश्व को एक मानवता के रूप में देखना शुरू करेंगे तभी नृशंस ताकतों के मुकाबले आधारभूत सिद्धान्तों और मूल्यों में विश्वास रखने वाले भारत जैसे देशों की ताकत का इजहार होगा। तभी विश्व वास्तव में रहने योग्य जगह बनेगा। यह दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों की सहायता करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि वहां उन पर अत्याचार किए जा रहे है। उनकी सहायता इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वे हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम सभी इन्सान हैं। इसीलिए हम उनकी सहायता कर रहे है। हम विश्व में कभी भी गलत रवैये के विरुद्ध इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम 'हमारे' और 'तुम्हारे' रवैये को मानवता के रवैये में बदलना चाहते हैं। इस काम को पंडित जी ने शुरू किया था और इसी काम को हमें आगे बढ़ाना है।

आज जब भारत बोलता है तो वह 1979 का भारत नहीं है जिसकी बात की कोई परवाह नहीं करता था। आज जब भारत बोलता है तो उसकी बात सुनी जाती है। उसे सुना जाता है। भारत महत्व रखता है। 1979 में अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत कोई महत्व नहीं रखता था। हम यह अन्तर ले आए हैं। अगर हम दोबारा अन्तर्मुखी हो जायेंगे, बाहर गलत नीतियों का अनुपालन करने लगेंगे तो हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां हम थे। हम विश्व की हंसी के पात्र बन जाएंगे। क्या हम अपने देश को पुनः उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गूंटूर) : नहीं, महोदय।

श्री राजीव गांधी : वर्तमान सरकार उसे उस स्थिति में लौटाने की अनुमति नहीं देगी।

निरस्त्रीकरण पर हमने एक बड़ी पहल की है। छह राष्ट्र पांच महाद्वीप शांति प्रयास ने

रेकजविक शिखर सम्मेलन के लिए वातावरण तैयार किया। हमें निराशा है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला पर हम पूरी तरह से हताश नहीं हैं क्योंकि अभी भी प्रस्ताव हैं। प्रमाणित करना एक बड़ी समस्या है। हम छह देशों ने कुछ हल सुझाए हैं। हम उस पथ पर चलते रहेंगे। हम मध्यम परमाणु अस्त्रों के बारे में इस नई पहल का, सोवियत संघ द्वारा की गई नई पहल का, स्वागत करते है और आशा करते हैं कि यह सफल होगी।

हम पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के प्रयास कर रहे हैं परन्तु कुछ गम्भीर समस्याएं अभी शेष हैं। परमाणु अस्त्र कार्यक्रम के लिए चोरी छिपे प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले बहुत से सालों से यह गति पकड़ रहा है। जिन पर इस कार्यक्रम को रोकने की जिम्मेवारी थी और जो ऐसा कर सकते थे वे ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में पाकिस्तान की सहायता की है।

प्रो० एन० जी० रंगा : शर्म की बात है।

श्री राजीव गांधी : आज हालत यह है कि परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ कानूनी बचाव होने के बावजूद पाकिस्तान को लगातार सफलता मिल रही है। यह बहुत असाधारण चीज हैं। अपनी प्रभुसत्ता और अखण्डता की रक्षा करने में भारत की जनता के दृढ़ निश्चय और क्षमता के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

दक्षिण में, श्रीलंका ने हमसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए कहा है और हमने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। काफी प्रगति हुई है जिसका परिणाम 19 दिसम्बर, 1986 के अन्तिम स्पष्टीकरण हैं। 19 दिसम्बर, 1986 के स्पष्टीकरणों का सम्बन्ध बहुत महीने पुराने ठोस प्रस्तावों से है। दुर्भाग्य से श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों से हमें बहुत दुःख पहुंचा है और उन्होंने इस प्रक्रिया को रोक दिया है। जब तक श्रीलंका में हिंसा की स्थिति जारी रहेगी तब तक उस प्रक्रिया को जारी रखना कठिन है। हम इस मामले को फिर से शुरु करें इससे पहले वहां हिंसा को रोका जाना चाहिए। हमने यह बात श्रीलंका सरकार को स्पष्ट कर दी है। यह स्पष्ट है कि हिंसा से कोई हल नहीं निकाला जा सकता। केवल अहिंसा और विचार-विमर्श से हल निकाला जा सकता है। हमने श्रीलंका सरकार से भी यह बात स्पष्ट कर दी है। हमें आशा है कि उन पर इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी और वे हिंसा को कम करेंगे तथा बातचीत के लिए राजी हो जाएंगे।

श्री पी० कुलनदईवेलु : पहले हम इस नरसंहार को क्यों नहीं रोकते ? सैनिक कार्यवाही जारी हैं।

श्री राजीव गांधी : वह हिंसा है।

श्री पी० कुलनदईवेलु : सैंकड़ों लोग मर रहे हैं। मैंने आज के अखबार में देखा हैं कि भारत के, प्रधानमंत्री के आह्वान की श्री जयवर्धने पर प्रतिक्रिया हुई है। मेरा अनुरोध हैं कि माननीय प्रधानमंत्री पहले हमें स्थिति से अवगत कराएं।

श्री राजीव गांधी : हमारे द्वारा राष्ट्रपति को पत्र भेजे जाने के बाद हिंसा में कमी आई है। लेकिन जितनी कमी अभी है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हमें आशा है कि हिंसा में और कमी आएगी और हम परस्पर विचार-विमर्श करके एक समझौता करने में समर्थ होंगे क्योंकि कोई और समझौता स्थायी समझौता नहीं होगा।

चीन के साथ सीमा पर तनाव है हम सीमा सम्बन्धी मसलों का शान्तिपूर्ण हल चाहते हैं। जरूरत संयम, बुद्धिमत्ता, राजनीतिज्ञता और शायद सबसे अधिक जरूरत दूरदर्शिता की है।

प्रो० मधु दण्डवते : और दृढ़ निश्चय की।

श्री राजीव गांधी : और दृढ़ निश्चय—यह बुद्धिमत्ता में आ जाता है।

हम दो प्राचीन सभ्यताएं हैं और हमें अपनी समस्याओं के हल इसी परिप्रेक्ष्य से खोजने हैं।

महोदय, राजनैतिक व्यवस्था का अस्तित्व नैतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। आजादी की हमारी लड़ाई सत्य और अहिंसा—इन दो मूल्यों पर आधारित थीं। अपने देश के निर्माण की प्रेरणा हमें इन मूल्यों से मिलती है। इसका उद्भव धैर्य, मेल-मिलाप, सभी धर्मों का समान विचारों के परस्पर सृजन के हमारे परम्परागत मूल्यों से हुआ है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हममें आत्मविश्वास होता है। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो हमें हमेशा यह डर लगा रहता है कि हम अपनी संस्कृति को, धर्म को खो बैठेंगे और हम आगे देखने के बजाय आत्मचिन्तन में खो जाते हैं। अपने को बचाने के लिए हम क्षेत्र, भाषा, धर्म और जाति की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। उसे तोड़ने के लिए हमें आज देश में इस आत्मविश्वास की जरूरत है। अपनी संस्कृति के अनिवार्य मूल्यों को बनाए रखने के लिए समय की मांग धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र में एकता है। पंडित जी ने कहा था कि हम तुच्छ लोग महान कार्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। काम महान है इसलिए उसकी कुछ महानता हमारे कन्धों पर आ गई है। हमें उसी भावना से डट कर, दृढ़ता तथा साहस से प्रयत्न करने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने बहुत से संशोधन रखे हैं। अब मैं सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रख दूं या कोई माननीय सदस्य किसी संशोधन विशेष को अलग से रखना चाहता है?

मैं देखता हूं कि कोई भी जोर नहीं दे रहा। अब मैं सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 17 से 278, 278 से 303 और 312 से 333 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

प्रो० मधु दण्डवते : अभी-अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि नरसंहार नहीं होना चाहिए लेकिन आपने सभी संशोधनों का गला घोंट दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा मैंने सदस्यों की सहमति से किया है ।

अब मैं मुख्य प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए : —

'कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 23 फरवरी, 1987 को एक साथ समवेत संसद को दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

1.13 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.20 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.20 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को लेते हैं । श्री राजकुमार राय ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में नकली दवाओं के उत्पादन को रोकने के लिए कठोर उपाय करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देता हूं :—

"दिल्ली प्रशासन ने 103 औषधि निर्माता कम्पनियों की जांच-पड़ताल की है । यह एक न केवल सामाजिक बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है कि औषधि निर्माण करने वाली